भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 246

19 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए नियत

दोपहिया वाहनों का विद्युत प्रारूप

246. डॉ. तालारी रंगैय्या:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का वर्ष 2030 तक दोपहिया श्रेणी के वाहनों को विद्युत चालित बनाने का कोई विचार है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा योजनाएं लागू की गई हैं; और

(ख) इन योजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को पारंपरिक अंतर्दहन इंजन वाले वाहनों के बराबर करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके अलावा, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वाहन उत्सर्जन संबंधी समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम की शुरुआत की। वर्तमान में, कुल 10,000/- करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम के द्वितीय चरण का कार्यान्वयन सम्पूर्ण भारत (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित) में किया जा रहा है। इस चरण का लक्ष्य सार्वजनिक और साझा परिवहन का विद्युतीकरण करना और 7090 इलेक्ट्रिक बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, 55,000 इलेक्ट्रिक चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोक्ताओं में रेंज संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता दी जाती है।

****